



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 ई0 (आश्विन 09, 1938 शक सम्वत्) [संख्या-40

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	479-486	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	677-688	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	225-227	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2

## कार्यालय-ज्ञाप

15 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 1088/XVI-2/16/17(15)/2015-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-167/01/डी0आर0/सेवा-02/2012-13, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उत्तराखण्ड रेशम विकास अधिकारी वर्ग "क" एवं "ख" सेवा नियमावली, 2011 के भाग-3, भर्ती का स्रोत-5 के परिशिष्ट "ख" के अन्तर्गत रेशम विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन सहायक निदेशक, रेशम (श्रेणी-ख) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति में से श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रकम सिंह, ग्राम नगला कोयल, पो0 गुरुकुल नारसन, जनपद हरिद्वार को संख्या 1062/XVI-2/15/17(15)/2015, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 द्वारा सहायक निदेशक, रेशम, वेतनमान ₹ 15,600-39,100+ग्रेड वेतन ₹ 5,400 में योगदान करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए नियमावली के भाग-6 के नियम 19(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत दो वर्ष की परीवीक्षा पर रखते हुए निर्देशित किया गया था कि वे अपनी योगदान सूचना 15 दिवस के अन्दर निदेशक, रेशम, प्रेमनगर, देहरादून के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त श्री कुलदीप सिंह द्वारा सहायक निदेशक, रेशम के पद पर योगदान न करते हुए अपने प्रत्यावेदन दिनांक 07.12.2015 योगदान देने हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में नियमानुसार शासन के पत्र संख्या 1289/XVI-2/15/17(15)/2015, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा श्री सिंह को योगदान देने हेतु 01 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

3. तदक्रम में पुनः श्री सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक शून्य के द्वारा योगदान देने हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में श्री सिंह को शासन के पत्र संख्या-18, दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा श्री सिंह को पुनः 01 माह का अतिरिक्त समय (दिनांक 01 फरवरी, 2016 तक) योगदान देने हेतु प्रदान किया गया, जिसके क्रम में श्री सिंह द्वारा पुनः अपने दिनांक रहित पत्र के माध्यम से अपरिहार्य व्यक्तिगत कारणों से योगदान देने हेतु 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या 479/XVI-2/16/17(15)/2015, दिनांक 19 अप्रैल, 2016 द्वारा श्री सिंह को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आप अपनी प्रथम नियुक्ति/तैनाती स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करें, निर्धारित समयावधि के भीतर यदि आपके द्वारा योगदान नहीं दिया जाता है तो यह मानते हुए कि सहायक निदेशक, रेशम के पद पर की गयी नियुक्ति हेतु आप इच्छुक नहीं हैं, तदनुसार आपका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा एवं आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी, योगदान हेतु समय प्रदान करने के लिए आपके द्वारा यदि पुनः अनुरोध किया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतः उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के क्रम में श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रकम सिंह, ग्राम नगला कोयल पो0 गुरुकुल नारसन, जनपद हरिद्वार के सहायक निदेशक, रेशम, वेतनमान ₹ 15,600-39,100+ ग्रेड वेतन ₹ 5,400 में नियुक्ति प्रदान किये जाने पर लगभग 07 माह से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने एवं आतिथि तक योगदान नहीं किये जाने के कारण श्री सिंह के नियुक्ति आदेश संख्या 1062/XVI-2/15/17(15)/2015, दिनांक 19 नवम्बर, 2015, को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव

एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।

## परिवहन अनुभाग-1

## अधिसूचना

09 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 614/IX-1/81/2015/2016—श्री राज्यपाल महोदय, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 217(1) एवं सपठित धारा 21, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 688/IX/435/2004, दिनांक 20 दिसम्बर, 2004, को अधिक्रमित करते हुए, यह निर्देश देते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में इंगित अधिकारी स्तम्भ-5 के अनुसार प्रत्येक धारा के समक्ष विनिर्दिष्ट धनराशि के लिए स्तम्भ-3 में उल्लिखित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का शमन कर सकेंगे:-

क्र० सं०	अधिकारी	धारा	अपराध का संक्षिप्त विवरण	प्रस्तावित प्रशमन शुल्क की नियत दरों (₹ में)
1	2	3	4	5
1.	नागरिक/यातायात पुलिस में नियुक्त अधिकारी, नियुक्ति के अन्तर्गत जो उप निरीक्षक से निम्न स्तर के न हों	धारा 177	बिना नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चलाना	100.00
		धारा 177 सपठित धारा 129	बिना हेलमेट के वाहन चलाना	100.00
2.		धारा 179 (1)	विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करना	500.00
3.		धारा 179 (2)	असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना	500.00
4.		धारा 184	मोटर वाहन खतरनाक प्रकार से चलाना/चलती वाहन में चालक द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना	1000.00
5.		धारा 186	शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने की हालत में वाहन चलाना	200.00
6.		केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम, 138(3) एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177	बिना सीट बेल्ट के मोटर वाहन चलाना	100.00

परन्तु नागरिक/यातायात पुलिस में नियुक्त राजपत्रित अधिकारी से भिन्न अधिकारी (जो स्तम्भ-2 में वर्णित है) केवल अपराध होते समय घटना स्थल पर ही उक्त प्रकार के प्रशमन के लिए अधिकृत होंगे।

आज्ञा से,  
चन्द्र सिंह नपलच्याल,  
सचिव।

## सूचना अनुभाग-01

## अधिसूचना/प्रकीर्ण

12 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 424/XXII(1)/2016-7(11)2012-श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015" एवं शासनादेश सं0 931/XXII/2016-7(11)2012, दिनांक 05 जनवरी, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्

नियम-10 का संशोधन-नियमावली में नियम-10, जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>10. विज्ञापन वितरण प्रक्रिया-</p> <p>प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन का प्रकाशन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। वर्गीकृत विज्ञापन का प्रकाशन सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं कराया जायेगा।</p>	<p>10. विज्ञापन वितरण प्रक्रिया-</p> <p>उत्तराखण्ड सरकार के समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। अनियमित समाचार-पत्रों को किसी भी दशा में विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे।</p>

नियम-13 (ग) का संशोधन-नियमावली में नियम-13(ग), जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>13(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निगम, उपक्रम, संस्था, बोर्ड, परिषद् एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये सजावटी विज्ञापन डी0ए0वी0पी0/विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा।</p>	<p>राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन डी0ए0वी0पी0/विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा। ऐसे निगम, उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएँ, परिषद्, बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकायों, जिनके विज्ञापन प्रमुख समाचार-पत्रों द्वारा डी0ए0वी0पी0/विभागीय दर पर प्रकाशित नहीं किये जाते हैं, वे स्वयं अपने स्तर से विज्ञापन प्रकाशन हेतु स्वतंत्र होंगे, ऐसे विज्ञापनों का भुगतान भी सम्बन्धित द्वारा किया जायेगा।</p>

नियम-15 (झ) का संशोधन-नियमावली में नियम-15(झ), जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
15(झ) वर्गीकृत विज्ञापनों का प्रकाशन एवं भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा।	समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों का भुगतान सूचना विभाग द्वारा किया जायेगा। सजावटी विज्ञापन का भुगतान मूलतः सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित विभाग के अनुरोध पर सूचना विभाग के द्वारा भी सजावटी विज्ञापन का भुगतान किया जा सकता है।

### अधिसूचना / प्रकीर्ण

15 सितम्बर, 2016 ई0

संख्या 425/XXII(1)/2016-7(11)2012-श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015" एवं अधिसूचना संख्या 101/XXII(1)/2016-7(11)2012, दिनांक 26 फरवरी, 2016 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0 273/XXII(1)/2016-7(11)2012, दिनांक 25 मई, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्-

नियम-4 का संशोधन-नियमावली में नियम-4, जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात्-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. सूचीबद्धता के लिए संचालन समिति-विज्ञापन हेतु समाचार-पत्रों की सूचीबद्धता एक समिति द्वारा की जायेगी। समिति में कुल 8 सदस्य होंगे, जिसमें से चार सरकारी तथा चार गैर सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी सदस्य नियम 5 के अनुरूप नामित पत्रकार होंगे। समिति निम्नवत् संरचित होगी:- (1) महानिदेशक, अध्यक्ष, (2) अपर निदेशक, सदस्य सचिव, (3) समिति में नामित चार पत्रकार सदस्य, (4) संयुक्त निदेशक अथवा उपनिदेशक (विज्ञापन), सूचना सदस्य, (5) सूचना अधिकारी, निरीक्षा शाखा सदस्य।	4. सूचीबद्धता के लिए संचालन समिति-विज्ञापन हेतु समाचार-पत्रों की सूचीबद्धता एक समिति द्वारा की जायेगी। समिति में कुल 13 सदस्य होंगे, जिसमें से 05 सरकारी तथा 08 गैर सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी सदस्य नियम 5 के अनुरूप नामित पत्रकार होंगे। समिति निम्नवत् संरचित होगी:- (1) महानिदेशक, अध्यक्ष, (2) अपर निदेशक, सदस्य सचिव, (3) प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन) सदस्य, (4) प्रभारी अधिकारी निरीक्षा शाखा सदस्य, (5) सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी सदस्य, (6) समिति में नामित पत्रकार (आठ) सदस्य।

नियम-5(क) का संशोधन-नियमावली में नियम-5(क), जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(क) समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल, चयन एवं पद से हटाया जाना-समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भारतीय प्रेस परिषद् से मान्यता प्राप्त प्रिंट मीडिया संगठनों के 02 पत्रकार तथा उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिंट मीडिया संगठनों के 02 पत्रकारों में से किया जायेगा। एक संगठन से केवल एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा।	5(क) समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल, चयन एवं पद से हटाया जाना-समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भारतीय प्रेस परिषद् से मान्यता प्राप्त प्रिंट मीडिया संगठनों के 02 पत्रकार तथा उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिंट मीडिया संगठनों के 02 पत्रकारों में से किया जायेगा। एक संगठन से केवल एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा। शेष चार पत्रकार मा0 सूचना मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किये जायेंगे।

नियम-8(छ) का संशोधन-नियमावली में नियम-8(छ), जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(छ) पूर्व से सूचीबद्ध समाचार-पत्रों की सूचीबद्धता नवीनीकरण की अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।	8(छ) पूर्व से सूचीबद्ध समाचार-पत्रों की सूचीबद्धता नवीनीकरण की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

नियम-11(ख) का संशोधन-नियमावली में नियम-11(ख), जो स्तम्भ-1 में दिये गये हैं, के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
11(ख) समाचार-पत्रों की निरीक्षा एवं नियमितता हेतु मापदण्ड-समाचार-पत्रों की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित समाचार-पत्र, पत्रिकाओं की 2 प्रतियाँ देहरादून स्थित सूचना विभाग के महानिदेशालय में प्रकाशन के 10 दिन के अन्दर तथा सम्बन्धित जिले के सूचना कार्यालय को प्रकाशन के 24 घण्टे के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। निर्धारित समयान्तर्गत समाचार-पत्र जमा न करने अथवा	11(ख) समाचार-पत्रों की निरीक्षा एवं नियमितता हेतु मापदण्ड-समाचार-पत्रों की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र, पत्रिकाओं की 2 प्रतियाँ देहरादून स्थित सूचना विभाग के महानिदेशालय की निरीक्षा में प्रकाशन के 10 दिन के अन्दर तथा सम्बन्धित जिले के सूचना कार्यालय को प्रकाशन के 24 घण्टे के अन्दर (यदि समाचार-पत्र का प्रकाशन जिला मुख्यालय से 30 किमी० की परिधि के भीतर होता हो) अथवा

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>एकमुश्त जमा किये जाने वाले समाचार-पत्रों को भी अनियमित माना जायेगा। समाचार-पत्र को सूचना विभाग के राज्य मुख्यालय तथा सम्बन्धित जिला सूचना कार्यालय अर्थात् दोनों स्थानों से नियमित होना आवश्यक है। ऑन लाइन नियमितता भी मान्य होगी। समाचार-पत्र के प्रकाशन की नियमितता प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। नियमितता के रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई समाचार-पत्र अनियमित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समाचार-पत्र के पुनःनियमित होने तक उसे विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे तथा वह समाचार-पत्र स्वतः ही विज्ञापन सूची से पृथक समझे जायेंगे। नियमितता प्रतिमाह के आधार पर तैयार की जायेगी।</p>	<p>48 घण्टे (यदि समाचार-पत्र का प्रकाशन जिला मुख्यालय से 30 किमी० से 50 किमी० की परिधि में होता हो) अथवा 72 घण्टे (यदि समाचार-पत्र का प्रकाशन जिला मुख्यालय से 50 किमी० से अधिक दूरी पर होता हो) जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवकाश होने पर वे अंक अगले कार्य दिवस पर जमा किये जा सकेंगे। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक समाचार-पत्रों को उनके अगले अंक के प्रकाशन के पूर्व यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित अंक की प्रतियाँ निःशुल्क उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। विलम्ब से जमा किये जाने वाले समाचार-पत्रों को नियमितता सूची में अंकित करने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों पर निर्णय लेने के लिए महानिदेशक, सूचना सक्षम प्राधिकारी होंगे। समाचार-पत्रों के प्रकाशन की नियमितता प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। समाचार-पत्र की नियमितता का आंगणन पिछले छः माह के प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर किया जायेगा। समाचार-पत्रों को विज्ञापन जारी करने हेतु सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी की नियमितता रिपोर्ट को ही आधार माना जायेगा परन्तु सूचना विभाग के राज्य मुख्यालय की निरीक्षा शाखा में नियमित रूप से समाचार-पत्र जमा न करने वाले समाचार-पत्रों को विज्ञापन सूची से पृथक करने का निर्णय महानिदेशक, सूचना द्वारा लिया जा सकता है।</p>

आज्ञा से,  
विनोद शर्मा,  
सचिव।

## उत्तराखण्ड जल संस्थान

## अधिसूचना

06 जुलाई, 2016 ई०

संख्या 913/उन्तीस (1)/2016/(59 पे०)/2004—पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1, देहरादून, दिनांक 06 जुलाई, 2016 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013, राजपत्र दिनांक 02-02-2013, भाग-1 में प्रकाशित टैरिफ के प्रस्तर-01 के क्रमांक 04 से 09, प्रस्तर-03 के क्रमांक 03 एवं 04 में अंकित श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं हेतु जलमूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि को घटाकर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा प्रस्तर-12 में उल्लिखित सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट चार्ज) के पेयजल उपभोक्ताओं हेतु 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के स्थान पर 09 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2016 से पुनरीक्षित किया जाता है। अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

एस० के० गुप्ता,

मुख्य महाप्रबन्धक।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 ई0 (आश्विन 09, 1938 शक सम्वत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

29 अगस्त, 2016 ई0

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), वाणिज्य कर,  
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 3374/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि-अनुभाग/पत्रा0/16-17/देहरादून-उत्तराखण्ड शासन के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 231/XXXVI(3)/2016/52(1)/2016 देहरादून, दिनांक 10 अगस्त, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016" सर्वसाधारण को सूचनार्थ हेतु अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

### उत्तराखण्ड शासन

#### विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 231/XXXVI(3)/2016/52(1)/2016

देहरादून, 10 अगस्त, 2016

#### अधिसूचना

##### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016" पर दिनांक 05 अगस्त, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016**  
(अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये—

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:—

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 31 का 2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—

31. कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने की शक्ति :—

(1) किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बन्ध में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हो, ब्यौहारी उक्त आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसा आदेश अपास्त करने और उस मामले पर पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, और यदि ऐसे अधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला था या वह पर्याप्त कारणों से नियत तारीख को उपस्थित न हो सका था, तो वह आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले की पुनः सुनवाई प्रारम्भ कर सकता है;

परन्तु यह कि इस प्रकार के एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी द्वारा सभी सावधिक विवरणियाँ तथा वार्षिक विवरणी पूर्ण एवं सही रूप में दाखिल न की गयी हो और उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे ब्यौहारी ने स्वीकार किया हो, भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण न हो;

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में, एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए, प्रार्थना पत्र केवल एक ही बार ग्रहण किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई एकपक्षीय आदेश 02 मार्च, 2016 को अथवा उसके पश्चात् तामील हुआ है और इस धारा के अधीन प्रार्थना पत्र, तामिली के 30 दिन समाप्त होने के भीतर अथवा इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के पूर्व, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, दाखिल किया जाता है, तो ऐसे एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया जायेगा बशर्त कि दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र इस उपधारा में विहित समस्त शर्तों को पूर्ण करता हो।

(2) यदि धारा 24 के अधीन कोई कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय दिया जाय, तो ब्यौहारी आदेश तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि ब्यौहारी ने ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित अन्तिम तारीख से तीस दिन के भीतर विवरणी प्रस्तुत करनी है और विवरणी के अनुसार देयकर का भुगतान कर दिया है, तो वह ऐसा आदेश और उसके अधीन मांग की सूचना भी, यदि कोई हो, परिष्कृत या अपास्त कर सकेगा।

परन्तु यह कि ऐसे मामले में, एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए, प्रार्थना पत्र केवल एक ही बार ग्रहण किया जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई एकपक्षीय आदेश 02 मार्च, 2016 को अथवा उसके पश्चात् तामील हुआ है और इस धारा के अधीन प्रार्थना पत्र, तामिली के 30 दिन समाप्त होने के भीतर अथवा इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के पूर्व, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, दाखिल किया जाता है, तो ऐसे एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया जायेगा बशर्त कि दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र इस उपधारा में विहित समस्त शर्तों को पूर्ण करता हो।

(3) यदि किसी ब्यौहार को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4-क के अधीन

पात्रता प्रमाण पत्र, उस अवधि के लिये दिया गया है जिसके लिये पात्रता प्रमाण पत्र दिये जाने के पूर्व कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश या अपील में आदेश पारित किया गया है, तो ऐसा आदेश उस कर निर्धारण या अपील प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता है, या तो स्वतः या ब्यौहारी के आवेदन पर, ऐसा पात्रता प्रमाण पत्र देने वाले आदेश की प्रति के उसको प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर, अपास्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार एक नया आदेश पारित किया जा सकता है :

परन्तु यह कि यदि ब्यौहारी द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन उपर्युक्त अवधि के भीतर किया गया हो, तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के बाद भी किया जा सकता है।

धारा 32(6) का 3.  
अन्तःस्थापन

“मूल अधिनियम” की धारा 32 की वर्तमान उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्—

(6) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश धारा 31 के अधीन अपास्त कर दिया जाय, तो उस वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश उस तारीख से, जब पूर्ववर्ती आदेश अपास्त किया गया था, तीन माह के भीतर किया जा सकता है।

धारा 61 में  
संशोधन

4. “मूल अधिनियम” की धारा 61 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

(1) प्रत्येक ब्यौहारी अपने कारोबार के दौरान रखे गये सभी लेखे जिनमें उत्पादन, स्टॉक, क्रय, परिधान या विक्रय से सम्बन्धित बिक्री बीजक, जमा पत्र नाम पत्र और बाउचर भी सम्मिलित हैं, कर निर्धारण वर्ष जिससे वे सम्बन्धित हों, की समाप्ति के पश्चात् 06 वर्ष की अवधि के लिए या ऐसे कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के पूरे होने तक, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, सुरक्षित रखेगा।

धारा 62 की 5.  
उपधारा (1) एवं  
(3) का संशोधन

"मूल अधिनियम" की धारा 62 की वर्तमान उपधारा (1) एवं उपधारा (3) निम्न प्रकार संशोधित कर दी जायेगी; अर्थात् -

(1) उपधारा (1) में शब्दावली "रुपये एक करोड़" के स्थान पर शब्दावली "रुपये पाँच करोड़" रख दी जायेगी।

(2) उपधारा (3) में शब्दावली "चालीस लाख से अधिक किन्तु रुपये एक करोड़ से अनधिक" के स्थान पर शब्दावली "एक करोड़ रुपये से अधिक किन्तु रुपये पाँच करोड़ से अनधिक" रख दी जायेगी।

आज्ञा से,  
रमेश चन्द्र खुल्वे,  
प्रमुख सचिव।

No.231/XXXVI(3)/2016/52(1)/2016  
Dated Dehradun, August 10, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Value Added Tax, (Second Amendment) Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 19 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 August, 2016.

## THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2016

(Act no. 19 of 2016)

An

Act

Further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty seventh year of  
the Republic of India, as follows :-

**Short title and commencement** 1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax, (Second Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force at once.

**Insertion of  
Section 31**

2. After the existing section 30 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, (hereinafter referred to as the "Principal Act"), the following section shall be inserted ; namely -

**31. Power to set aside an Order of Assessment :**

(1) In any case in which an order of assessment or reassessment or order of penalty is passed ex- parte, the dealer may apply to the Assessing Authority within thirty days of the service of the order to set aside such order and reopen the case; and if such officer is satisfied that the applicant did not receive notice or was prevented by sufficient cause from appearing on the date fixed, he may set aside the order and reopen the case for hearing;

Provided that no such application for setting aside such ex-parte order shall be entertained unless the dealer has submitted all periodical returns and Annual Return completely and correctly and it is accompanied by satisfactory proof of the payment of the amount of tax admitted by the dealer to be due;

Provided further that in such case, the application for setting aside an ex-parte order, shall be entertained only once.

Provided further that if an ex-parte order is served on or after 2<sup>nd</sup> March, 2016 and an application under this Section is submitted before the expiry of 30 days from the date of service of order or before 30 days of the issuance of this notification,

whichever is later, the application to set aside such ex-parte order shall be entertained provided that the application submitted fulfills all the conditions laid down under this sub-section.

(2) Where an assessment order under Section 24 is passed ex-parte the dealer may apply to the Assessing Authority within thirty days of the service of the order, to set aside such order and if such authority is satisfied that the dealer has filed the return and deposited the tax due according to the return within thirty days from the last day prescribed for filing such return, it may modify or set aside such order and also the demand notice, if any, issued thereunder.

Provided that in such case, the application for setting aside an ex-parte order, shall be entertained only once.

Provided further that if an ex-parte order is served on or after 2<sup>nd</sup> March, 2016 and an application under this Section is submitted before the expiry of 30 days from the date of service of order or before 30 days of the issuance of this notification, whichever is later, the application to set aside such ex-parte order shall be entertained provided that the application submitted fulfills all the conditions laid down under this sub-section.

(3) If a dealer is granted an eligibility certificate under Section 4-A of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 for the period for which an order of assessment or reassessment or an order in appeal has been passed prior to the grant of eligibility certificate, such order may be set aside either on its own or on the application of the dealer, by Assessing or Appellate Authority having jurisdiction within one year of receipt by him of the copy of the order granting such eligibility certificate and a fresh order may be passed according to law;

Provided that where the application under this section has been made by the dealer within the period aforesaid, it may be disposed of even beyond such period.

Insertion of  
Section 32(6)

3. After the existing sub-section (5) of section 32 of the "Principal Act", the following sub-section shall be inserted; namely—
- (6) If an order of assessment or reassessment for any assessment year is set aside under Section 31, a fresh order of assessment or reassessment for that year may be made within three month from the date on which such earlier order was set aside.

Amendment  
in Section 61

4. For the sub-section (1) of Section 61 of the "Principal Act", the following sub-section shall be substituted; namely —
- (1) Every dealer shall preserve all accounts required to be maintained by him in the course of his business, including sale invoices, debit credit memos and vouchers relating to productions, stocks, purchases, deliveries and sales, for a period of six years after the close of the assessment year to which they relate or till the assessment or reassessment or any other proceedings under the act for such assessment is completed, whichever is later.

Amendment of  
sub-section (1)  
and sub-section  
(3) of Section 62

5. The existing sub-section (1) and sub-section (3) of Section 62 of the "Principal Act" shall be amended as follows; namely-
- (1) In sub-section (1), the words "one crore rupees" occurring the words "five crore rupees" shall be substituted.
- (2) In sub-section (3), the words "exceeds forty lakh rupees but does not exceed one crore rupees" occurring the words "exceeds one crore rupees but does not exceed five crore rupees" shall be substituted.

By Order,

RAMESH CHANDRA KHULBE,  
Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,

एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,

मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर****कार्यालय आदेश**

22 अगस्त, 2016 ई०

पत्रांक 2034/टी०आर०/पंजी०नि०/HR38A-7329/2016—वाहन संख्या HR38A-7329, मॉडल 1996, चेसिस संख्या 365352GTQ009181 तथा इंजन नं० 697D28FTQ13163, कार्यालय में श्रीमती शालू एवं श्रीमती रचना बब्बर पत्नी श्री परवेश एवं श्री नरेश बब्बर, निवासी आदर्श कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.08.2016 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/परमिट जारी नहीं हुआ आदि की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38A-7329 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 365352GTQ009181 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

**कार्यालय आदेश**

22 अगस्त, 2016 ई०

पत्रांक 2035/टी०आर०/पंजी०नि०/UA06-9125/2016—वाहन संख्या UA06-9125, मॉडल 1993, चेसिस संख्या 357011K93810636 तथा इंजन नं० 697SP21K93718848, कार्यालय में गुरुनानक देव पब्लिक स्कूल, नानकपुरी टाडा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 08.08.2016 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/परमिट जारी नहीं हुआ की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06-9125 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357011K93810636 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), काशीपुर****कार्यालय आदेश**

14 सितम्बर, 2016 ई०

पत्रांक 397/टी०आर०/कर-पंजीयन/UA04 3783—वाहन संख्या UA04 3783 बस, मॉडल 2000, चेसिस नं० 359350CUQ002821 इस कार्यालय में श्री सनतोक सिंह पुत्र श्री आंचल सिंह, निवासी म० नं० 88, गोपीपुरा, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 15.07.2016 को आवेदन-पत्र के साथ मूल चेसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है, कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, अनिता चन्द, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA04 3783 बस का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 359350CUQ002821 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी  
(प्रशासन), काशीपुर।

**कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश**  
**आदेश**

07 सितम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 1104/प्रशा0/ला0/2016-विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेंसधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। लाइसेंसधारकों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में डा0 अनीता चमोला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित लाइसेंसों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ:-

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	कृत कार्यवाही निलम्बित
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अजय पाल सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी-किरारा, पो0 चाका, टिहरी गढ़वाल	यूके-1420060050571, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	01.09.2016 से 01.10.2016 तक निलम्बित
2.	श्री हरीश लाल पुत्र श्री धन्ना लाल, निवासी-330, लक्ष्मण रोड, ऋषिकेश	यूके-1420070011094, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	03.09.2016 से 02.10.2016 तक निलम्बित
3.	श्री महेश सिंह पुत्र श्री देव सिंह, निवासी-कंडियाल गाँव, टिहरी गढ़वाल	यूके-14199500035501, मोटर साइकिल, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग	प्रवर्तन अधिकारी से दुर्व्यवहार	06.09.2016 से 05.12.2016 तक निलम्बित
4.	श्री केवल कुमार पुत्र श्री हरि लाल, निवासी-496, बनखण्डी, ऋषिकेश	यूके-142006067621, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
5.	श्री सुल्तान सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी-गुमानीवाला, ऋषिकेश	यूके-1420050031177, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित

1	2	3	4	5	6
6.	श्री चन्दन पुत्र श्री रामपाल, निवासी-48, केशवपुरी, डोईवाला, देहरादून	यूके-1420070038117, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
7.	श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश, निवासी-14 बीघा, मुनि की रेती, ऋषिकेश	यूके-1420110021669, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी	परमिट शर्तों का उल्लंघन	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
8.	श्री भूरा लाल पुत्र श्री सुन्दर लाल, निवासी-ओटान बगसील, टिहरी गढ़वाल	यूके-1420080028898, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
9.	श्री चेत राम पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी-काली कमली वाली, धर्मशाला, ऋषिकेश	यूके-1419870043969, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुड़की	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
10.	श्री केदार सिंह पुत्र श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम गमदिड, गाँव पो0 साल्ड, उत्तरकाशी	यूके-1420020045910, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
11.	श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री जबर सिंह, निवासी-ग्राम डागर, पो0 दुआधार, टिहरी गढ़वाल	यूके-1419920031958, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
12.	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री देव सिंह, निवासी-लदाडा, पो0 धनारी, उत्तरकाशी	यूके-1420050023819, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
13.	श्री विजय कुमार पुत्र श्री बी0 डी0 कुमार, निवासी-थरसाडा, उत्तरकाशी	यूके-1419930050609, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित

1	2	3	4	5	6
14.	श्री होशियार सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी-ग्राम कठियाड, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल	यूके-1420030055442, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक)	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी	क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
15.	श्री नवीन पुत्र श्री भोला दत्त, निवासी-अदूरवाला, भानियावाला, ऋषिकेश, देहरादून	यूके-1420080002582, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	सिटी पेट्रोल यूनिट, देहरादून	नियमों का उल्लंघन	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
16.	श्री नवल राणा पुत्र श्री खडक शमशेर राणा, निवासी-134, साहब नगर, छिदरवाला, ऋषिकेश	यूके-1420130060581, मोटर साइकिल एवं मोटर कार	यातायात पुलिस, देहरादून	नियमों का उल्लंघन	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
17.	श्री प्रतीक रावत पुत्र श्री दुर्गा सिंह रावत, निवासी-100, आशुतोष नगर, ऋषिकेश	यूके-1420130060176, मोटर साइकिल एवं मोटर कार	सिटी पेट्रोल यूनिट, देहरादून	नियमों का उल्लंघन	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित
18.	श्री विजय पुत्र श्री मीन बहादुर, निवासी-ढालवाला, मुनि की रेती, ऋषिकेश	यूके-1420070003083, हल्का मोटर वाहन (गैर परिवहन), हल्का मोटर वाहन (व्यवसायिक), परिवहन यान	यातायात पुलिस, देहरादून	नियमों का उल्लंघन	06.09.2016 से 05.11.2016 तक निलम्बित

डा0 अनीता चमोला,  
लाइसेंसिंग प्राधिकारी/  
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
ऋषिकेश।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 ई0 (आश्विन 09, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि  
कार्यालय नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़)

03 अगस्त, 2016 ई0

पत्रांक 101/भवन कर/उपविधि/शासकीय प्रकाशन/2016-17—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) 1916 की धारा 128(1) के, जो कि नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़) में अपनी सीमान्तर्गत गृह कर (भवन कर) नियमावली जिसका उल्लेख निम्न है, बनाई है। उक्त अधिनियम की धारा 133(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए। नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़) उप-विधि की पुष्टि करते हैं। जो जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार-पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्ति अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़) को प्रेषित की जा सकेगी, निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह उपनियम शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवन कर उपविधि 2017-18 से प्रभावी

1. नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़) की सीमा में सभी मकानों, इमारतों तथा भूमियों के वार्षिक किराये के मूल्य की 10 प्रतिशत भाग का 10 प्रतिशत तक भवन कर के रूप में देय होगा पर इस में निम्नलिखित अपवाद होंगे:—

(अ) ऐसी सभी भूमि व भवन, जिनके वार्षिक किराये का मूल्य ₹ 10,000 (दस हजार रुपये) से कम हो।

(ब) जो भवन सरकारी सम्पत्ति होगी और किराये के लिए नहीं है अर्थात् जिन्हें किराये पर साधारणतया नहीं दिया जा सकता हो।

(स) मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, विद्यालय, होस्टल तथा धर्मशाला।

(द) भवन व भूमि जो मन्दिर और मस्जिद की है।

2. (अ) वार्षिक किराये का मूल्य का तात्पर्य कॉलेजों, धर्मशालाओं, अस्पतालों, कारखानों, होटलों, गोदाम तथा इसी प्रकार के दूसरे व्यावसायिक भवनों की दशा में भवन निर्माण का वर्तमान अनुमानित लागत और उसके सम्बन्धित भूमि के मूल्य के योग के 5 प्रतिशत के 10 प्रतिशत से होगा।
- (ब) ऐसे भवन जो उक्त नियम (अ) के अन्तर्गत न आते हो, उसकी वार्षिक किराये की कीमत यह समझी जायेगी, जिस पर यह वास्तव में दी गई हो। उसमें यदि फर्नीचर व मशीनरी यदि कोई किराये में शामिल हो तो उतना किराया घटा दिया जायेगा। यदि उसमें मकान मालिक स्वयं रहता हो तो कच्चे मकान पर ₹ 70.00 प्रति कमरा एवं पक्के मकान पर ₹ 80.00 प्रति कमरा भवन कर आरोपित किया जायेगा।
3. भवनकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक देय होगा। इसके पश्चात् जमा करने पर भवनकर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पैनल्टी के रूप में देय होगा।
4. भवन में उसका आँगन भी सम्मिलित होगा (यदि हो)।
5. शासकीय भूमि एवं अन्य प्रकार की भूमि पर निर्मित भवनों पर लगे भवनकर को मालिकाना हक का आधार नहीं माना जायेगा एवं भवनकर नामान्तरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया जैसे (म्युनिसिपल ऐक्ट 1916 की धारा 147(2) विज्ञप्ति प्रकाशित कर नामान्तरण हेतु अन्तिम निर्णय नगर पालिका परिषद्, धारचूला बोर्ड का होगा। किसी भी रूप में भवनकर रसीद मालिकाना हक के अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं होगी।
6. ऐसी सम्पत्ति जिस पर कर लगाया गया हो, के स्वामी को करदाता समझा जायेगा—
  - (अ) साधारणतया कर निर्धारण भूमि और मकान के वास्तविक अधिकारी के नाम किया जायेगा। यदि ऐसा व्यक्ति सम्बन्धित भूमि और भवन कर स्वामी हो या राज्य सरकार अथवा नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़) अथवा किसी व्यक्ति द्वारा लीज पर दी गई भूमि का उपयोग कर रहा हो।
  - (ब) निम्नलिखित दशा में कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी के नाम किया जायेगा:—
    - (1) यदि सम्पत्ति किराये पर दे दी गई हो।
    - (2) यदि किराये पर ली गई सम्पत्ति को मूल किरायेदार ने दूसरे किसी व्यक्ति को किराये पर दे दी हो।
    - (3) यदि ऐसे व्यक्ति ने जिसे सम्पत्ति किराये पर देने का अधिकार हो, सम्पत्ति किराये पर न दी हो।
    - (4) यदि किसी भूमि अथवा मकान का स्वामी कर अदा करने में असमर्थ हो तो सभी सम्बन्धित भवन का कर नगर पालिका परिषद्, धारचूला (पिथौरागढ़) उस व्यक्ति से वसूल कर सकती है। जिसके अधिकार में वह भवन उस समय हो, परन्तु ऐसा व्यक्ति अपने अधिकार में लिए हुए भाग के केवल उतने ही भाग से वार्षिक मूल्य कर सूची द्वारा प्रमाणित कराकर अदा करेगा, जितने पर वह अधिकार रखता है।
7. ऊपर लिखे उपनियमों के अन्तर्गत कर अदा करने वाला व्यक्ति, जो वास्तविक करदाता नहीं है, अपने द्वारा अदा किये गये कर को वास्तविक करदाता से वसूल करने का अधिकारी होगा।
8. यह कि कर पाँचवें वर्ष अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी व बोर्ड द्वारा कर निर्धारण के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों के द्वारा कर निर्धारण किया जायेगा। कर सूची हर पाँचवें वर्ष 31 जनवरी के पूर्व तैयार होगी, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी:—
  - (अ) जिस मुहल्ले में स्थित हो, उसका नाम।
  - (ब) सम्पत्ति का नाम, पद या नम्बर जिससे उसकी पहचान हो सके।
  - (स) मालिक एवं उसमें रहने वाले का नाम।
  - (द) सम्पत्ति के वास्तविक किराये का मूल्य।
  - (य) उस पर लगाया गया कर।
9. 31 जनवरी या उससे पूर्व अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी या बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति कर निर्धारण व्यक्तियों की एक सूची इन नियमों से सम्बन्धित फार्म में तैयार करेंगे जिसमें करदाता और उस सम्पत्ति का विवरण होगा जिस पर कर हो, सूची में तैयारी कर नये प्रकार से लगाया जायेगा भले ही पिछली सूचियों की प्रविष्टियों से सहायता ली जाय।
10. सूची तैयार होने पर जनता को सूचना दी जायेगी कि अमुक स्थान पर सूची अथवा उसकी नकल देखी जा सकती है। करदाता व उसके प्रतिनिधि उसकी निःशुल्क देखने के अधिकारी होंगे।

11. (अ) अध्यक्ष या अधिशासी अधिकारी सूची तैयार होने पर प्रकाशन के दिनांक से एक माह की नोटिस उस समय देगा जब वह लगाये गये टैक्स पर विचार करेगा, ऐसा करना उस स्थिति में अति आवश्यक है, जब किसी सम्पत्ति पर पहली बार टैक्स लगाया जा रहा हो या टैक्स पहले की अपेक्षा बढ़ाया जा रहा हो।  
(ब) कर सूची पर आपत्तियाँ लिखित रूप में कारण सहित इस उद्देश्य के लिए निश्चित हुई तिथि के भीतर करनी होगी।  
(स) अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी बोर्ड द्वारा कर निर्धारण के लिए नियुक्त की गई समिति, प्रार्थी को उसके बयान के अवसर पर आवश्यक छान-बीन करके उसकी आपत्ति का निराकरण करेंगे और आवश्यक परिवर्तन सूची में करेंगे।
12. बोर्ड किसी भी समय पर्याप्त कारणों के आधार पर सूची में परिवर्तन कर सकता है, जिसमें करदाता का नाम घटाया बढ़ाया जा सकता है और टैक्स में परिवर्तन किया जा सकता है।
13. कर-निर्धारण अधिकारी 31 मार्च अथवा उसमें पूर्व कर सूची को अन्तिम रूप में अवश्य तैयार करेगा।
14. बोर्ड किसी भी समय उचित एवं पर्याप्त कारण के आधार पर सूची संशोधन कर सकता है या संशोधन में किसी का नाम जोड़ कर या काट कर या सम्पत्ति व उसके मूल्य में परिवर्तन कर सकता है।
15. (अ) यदि किसी ऐसी सम्पत्ति, भूमि, भवन जिस पर टैक्स लगता हो, का स्वामित्व अथवा टैक्स देने सम्बन्धी अधिकार परिवर्तन हो जाय तो वह व्यक्ति, जो उसका अधिकारी बन रहा हो, तत्सम्बन्धी अधिकार पत्र लिखे जाने के बाद या पंजीकरण के बाद (यदि पंजीकरण हुआ हो), स्थानान्तरण के बाद यदि अधिकार कम न लिखा गया हो, 13 महीने के भीतर इस अधिकार परिवर्तन की सूचना लिखित रूप में अधिशासी अधिकारी को देगा।  
(ब) यदि किसी भूमि व भवन स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अधिकारी व उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार अपने अधिकार प्राप्त करने के तीन माह के अन्दर लिखित सूचना अधिशासी अधिकारी को देगा।  
(स) अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के पूछे जाने पर उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
16. पूर्व लिखित नियमों के आधार पर जो व्यक्ति अधिकार पाने की सूचना देगा, वह उस सम्पत्ति पर लगाये गये टैक्स का बकाया अदा करके ₹ 1500 भवनकर नामान्तरण फीस तथा विज्ञप्ति प्रकाश व्यय अदा करना होगा।
16. (1) बिक्रय भूमि अन्य के नाम परिवर्तन करने पर 50 वर्ग मी0 तक ₹ 2000 तथा 100 वर्ग मी0 तक ₹ 3000 तथा 200 वर्ग मी0 तक ₹ 4000 तथा 200 वर्ग मी0 से अधिक ₹ 5000 कर नामान्तरण शुल्क देय होगा। प्रकाशन व्यय अतिरिक्त देय होगा।
17. (अ) अधिकार परिवर्तन का प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत होगा।  
(ब) उत्तराधिकारी के विषय में संशय होने पर मामला बोर्ड के विचाराधीन होगा, जिसका निर्णय तब तक मान्य होगा जब तक कोई अधिकार प्राप्त न्यायालय इस विषय में निर्णय न दे दे।
18. कर वसूली म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की संहिता 6 के अनुसार होगी।

#### दण्ड

उत्तराखण्ड में प्रवृत्त म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 (1) के अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि ऊपर लिखे गये नियमों की अवहेलना का दण्ड पाँच हजार रुपये (₹ 5000) तक होगा, अवहेलना लगातार जारी रही तो प्रथम दण्ड के पश्चात् उक्त अवधि में जिसमें अपराधी का अपराध किया जाना सिद्ध हो जाय, ₹ 25 (पच्चीस रुपये) प्रति दिन जुर्माना हो जायेगा।

डी0 के0 तिवारी,  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्, धारचूला,  
(पिथौरागढ़)।

दशरथी खैर,  
अध्यक्ष,  
नगर पालिका परिषद्, धारचूला,  
(पिथौरागढ़)।